

नई शिक्षा नीति

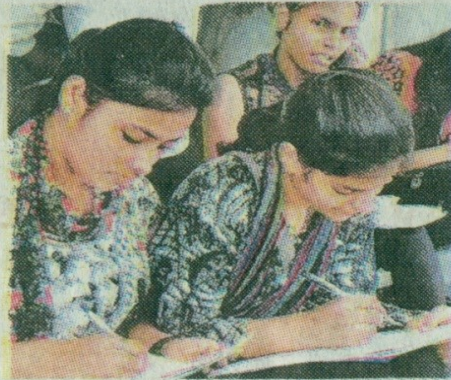
मोदी शासन में शिक्षा में बदलाव पर शिक्षाविदों की राय

निजीकरण और अवैज्ञानिक सोच को बढ़ावा

डेली न्यूज नई दिल्ली ▷ 16 जुलाई

देश के जानेमाने शिक्षाविदों और शिक्षा संगठनों ने कहा है कि मोदी सरकार नई शिक्षा नीति की आड़ में अंधाधुंध निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। अवैज्ञानिक सोच को स्थापित कर शिक्षक समुदाय को भी दो भागों में बांटना चाहती है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ (फेडकुटा) की ओर से नई शिक्षा नीति के मसौदे पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ताओं ने यह बात कही। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश, मिजोरम जैसे राज्यों से आए शिक्षक नेताओं के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर



लाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शांति निकेतन एवं गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने इसमें भाग लिया।

स्वायत्तता की आड़ में निजीकरण

सम्मेलन में वक्ताओं का कहना था कि नई शिक्षा नीति के प्रारूप में कॉलेजों को स्वायत्तता देने के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा देने और प्रतिगामी मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें न तो फंडिंग का जिक्र है और न ही वैज्ञानिक सोच का उल्लेख है, इससे पता चलता है कि मोदी सरकार इसकी आड़ में अपने एजेंडे को लागू करना चाहती है।

कापेरिट के हाथ में शिक्षा

अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ के महासचिव डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि जर्मनी जैसे पूंजीवादी देश में शिक्षा निशुल्क है और सार्वजनिक क्षेत्र में है, जबकि हमारे देश में शिक्षा पूरी तरह कापेरिट के हाथ में चला गया है। नई शिक्षा नीति पूरी तरह दिखावा है। इसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और वैज्ञानिक सोच जैसे संवैधानिक मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें सामाजिक न्याय का भी ख्याल नहीं रखा गया है, बल्कि अवैज्ञानिक नजरिए को बढ़ावा दिया गया है और सरकार विश्व व्यापार संगठन तथा गैट के इशारे पर कम कर रही है।